

प्रेषक,

डा० एम०सी० जोशी,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।

वित्त(वे०आ०-सा०नि०)अनुभाग-7

देहरादून: दिनांक: 30 अक्टूबर, 2015

विषय:- अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2014-2015 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उत्पादकता से जुड़ी किसी भी बोनस योजना के अन्तर्गत न आने वाले उपर्युक्त श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बोनस की विस्तृत योजना के अभाव में शासनादेश संख्या-252/XXVII(7)बोनस/2012 दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 द्वारा राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों, कार्यप्रभारित एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2013-2014 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस भुगतान के आदेश जारी किये गये थे।

2- भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सेवा के कर्मचारियों को कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16 अक्टूबर, 2015 द्वारा वर्ष 2014-2015 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस की स्वीकृति के आदेश जारी किये गये हैं।

3- उक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 के क्रम में राज्य सरकार के समस्त पूर्णकालिक राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित कर्मचारियों, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के ऐसे

कर्मचारियों, जिनके द्वारा धारित पद का अधिकतम ग्रेड वेतन रु0 4800/- (पूर्ववर्ती अपुनरीक्षित वेतनमानों में जिनके वेतनमानों का अधिकतम रु0 13,500/- से कम है), में है तथा जो अराजपत्रित श्रेणी में हों, को वर्ष 2014-2015 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस की निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. नई वेतन संरचना के अन्तर्गत ग्रेड वेतन रु0 4800/- तक के पद (पूर्व अपुनरीक्षित वेतनमानों में, जिनके वेतनमान का अधिकतम रु0 13500/- से कम है) में कार्यरत ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों, जिन्हें उपरोक्त ग्रेड वेतन/वेतनमान से उच्च ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान, समयमान वेतनमान अथवा वित्तीय स्तरान्वयन के रूप में अनुमन्य हुआ हो और उनकी प्रास्थिति (स्टेटस) में परिवर्तन न हुआ हो, को भी तदर्थ बोनस अनुमन्य होगा।
2. इन आदेशों के अन्तर्गत केवल वही अराजपत्रित कर्मचारी बोनस सुविधा हेतु पात्र होंगे, जो दिनांक 31 मार्च, 2015 को राज्य सरकार की नियमित सेवा में थे और जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2015 तक न्यूनतम छः माह की लगातार सेवा पूर्ण कर ली हो। वर्ष के दौरान न्यूनतम छः महीने से पूरे एक वर्ष तक लगातार सेवा की अवधि के लिए पात्र कर्मचारियों को आनुपातिक अदायगी स्वीकार्य होगी, पात्रता अवधि की गणना सेवा के महीने (महीनों की निकटतम संख्या में पूर्णांकित) की संख्या में की जायेगी।
3. तदर्थ बोनस के लिए एक माह में औसत दिनों की संख्या-30.4 के आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2015 को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियाँ आगणित की जायेगी।
4. दिनांक 31 मार्च, 2015 को वास्तविक औसत परिलब्धियाँ रु0 3500/- से ज्यादा होने की स्थिति में रु0 3500/- की परिकल्पित परिलब्धि मानकर दिनांक 31 मार्च, 2015 को 30 दिन की परिलब्धियाँ $(\text{रु0 } 3500 \times 30 / 30.4 = 3453.9)$ अर्थात् 3454/- तदर्थ बोनस के रूप में अनुमन्य होगी। तदर्थ बोनस की आगणित धनराशि को निकटतम एक रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा।
5. ऐसे कर्मचारी, जिनके विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमावली के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लम्बित हो, को तदर्थ बोनस का भुगतान, ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा मुकदमे का परिणाम प्राप्त होने तक स्थगित रहेगा, जो दोषमुक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त जिन कर्मचारियों को वर्ष 2014-15 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अपराधिक मुकदमे में दण्ड दिया गया हो, उन्हें तदर्थ बोनस देय न होगा।
6. किसी वित्तीय वर्ष के तदर्थ बोनस के सम्बन्ध में एक बार निर्णय ले लिये जाने के पश्चात आगामी वर्षों में किसी भी परिस्थिति में पुनर्विचार नहीं किया जायेगा।

4- दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2015 को 03 वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हो, को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसी पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी, जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2015 तक एक वर्ष निरन्तर सेवा पूरी नहीं की है, परन्तु उक्त तिथि तक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में (दोनों अवधियों को सम्मिलित करते हुए) 03 वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिनांक कार्यरत रहे हों, यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे मामले में सम्बन्धित कर्मचारी के लिये मासिक परिलब्धियां रू0 1200/- प्रतिमाह मानी जायेगी और इस प्रकार तदर्थ बोनस की देय धनराशि रू0 1200X30/30.4=1184.21 अर्थात् 1184/- पूर्णांकित होगी, परन्तु ऐसे कर्मचारी जिनकी वास्तविक परिलब्धियों रू0 1200/- प्रतिमाह से कम हैं उन्हें तदर्थ बोनस की धनराशि उनकी वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर आगणित की जायेगी।

5- उक्तानुसार स्वीकृत तदर्थ बोनस का भुगतान नकद रूप में किया जायेगा।

6- बोनस के भुगतान से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-वे0आ0-1-120/दस-1(एम)/84, दिनांक 18 जनवरी, 1984 के प्रस्तर-1 (7), 5 तथा 6 में उल्लिखित शर्तें एवं प्रतिबन्ध इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस के विषय में भी यथावत् लागू रहेंगे।

7- उक्त स्वीकृत तदर्थ बोनस को आय व्ययक के सुसंगत लेखाशीर्षक के मानक मद "वेतन" के अन्तर्गत पुस्तांकित किया जायेगा।

भवदीय,

(डा0 एम0सी0 जोशी)
सचिव।

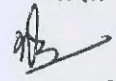
संख्या: २१२ (1)/XXVII(7)बोनस/2012-15 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग/शहरी विकास विभाग/पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रमों में यदि बोनस की देयता हो और सम्बन्धित निकाय/उपक्रम उक्त व्ययभार को वहन करने में सक्षम हो तो कृपया अपने स्तर से उक्त वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपने अधीनस्थ निकाय/उपक्रमों में नियुक्त कार्मिकों को तदर्थ बोनस

अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं। उक्त सम्बन्ध में पुनः वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. निबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
6. मुख्य स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं-261, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001।
8. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, देहरादून।
9. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं वित्त सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
12. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
13. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस शासनादेश की 100 प्रतियाँ मुद्रित कर वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
14. निदेशक, एन०आई०सी०, देहरादून।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा० एम०सी० जोशी)
सचिव।